



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2005/आषाढ़ 24, 1927

No. 105]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2005/ASADHA 24, 1927

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 11 जुलाई, 2005

सं. टीएमपी/29/2005-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, आयातीत कोक और कोकिंग कोयला पत्तन से खाली करने में हुए अतिविलम्ब के लिए अर्थदंड/अचल-उपकर लगाने के लिए पारादीप पत्तन न्यास के प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएमपी/29/2005-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास

आदेश

आवेदक

(जून 2005 के 15वें दिन पारित)

यह प्रकरण आयातीत कोक और कोकिंग कोयला पत्तन से खाली करने में हुए अति विलम्ब के लिए अर्थ दंड / अचल उपकर लगाने के लिए पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. पीपीटी द्वारा प्रस्तुत किए गए मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:

- (i) आयातकों / निर्यातकों द्वारा आयातीत कोयला और कोक हटाने में असाधारण विलम्ब किए जाने के कारण सण्डारण याडों / भूखण्डों में जगह की तंगी महसूस की जा रही है।
- (ii) यदि आयातीत कार्गो 60 दिन के भीतर नहीं हटा लिया जाता है तो महापत्तन न्यास अधिनियम पत्तन न्यास को आयातीत कार्गो नीलाम करने का अधिकार देता है। इस प्रकार की कार्रवाई करने से निर्यातक / आयातक समुदाय की ओर कठोर प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं। इस प्रकार कोई अन्य विकल्प शेष न पाकर, पीपीटी यह प्रस्ताव तैयार लेकर आया है।
- (iii) 7 अक्टूबर 2004 को आयोजित बैठक में पीपीटी ने कोयले और कोकिंग कोयले के निर्यातकों से, कार्गो हटाने में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड लगाना और कार्गो को शीघ्र ही हटाने पर रियायत देना आरम्भ करने पर सलाह मशविरा किया था। पत्तन के अनुसार उपयोगकर्ता अर्थदंड और रियायत की दरों पर सहमत हो गए हैं।
- (iv) आयातीत कोक और कोकिंग कोयले को पत्तन से हटाने में असाधारण विलम्ब के लिए पत्तन निम्नलिखित अर्थदंड / अचल उपकर लगाने का प्रस्ताव करता है और प्रभारों की बसूली तदर्थ आधार पर होगी:

हटाने / खाली करने की अवधि	अर्थदंड / अचल उपकर
पोत से पूरा कार्गो उतरने के 45 दिन के भीतर	कोई नहीं
46 वे दिन से 90 वे दिन तक	रु. 5/- प्रति टन
91 वे दिन से 120 वे दिन तक	रु. 10/- प्रति टन
121 वे दिन और उसके बाद	रु. 20/- प्रति टन

- (v) (क) हरा राबंध में वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए राजस्व उत्पादन की गणना पत्तन से कार्गो के निम्नलिखित औरत मात्रा में हटाए जाने के आधार पर की गई है:
- |                               |     |
|-------------------------------|-----|
| (क) 45 दिन के भीतर            | 80% |
| (ख) 45 से 90 दिन के भीतर      | 10% |
| (ग) 91 दिन से 120 दिन के भीतर | 8%  |
| (घ) 121 दिन और उससे अधिक      | 2%  |
- (ख) प्रस्तावित अर्थदंड लगाने की मद में राजस्व-उत्पादन निम्नानुसार होगा:
- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| वर्ष 2005-06 | 62.90 लाख रुपये |
| वर्ष 2006-07 | 68.00 लाख रुपये |
- (vi) पीपीटी के न्यासी मंडल ने 25 जनवरी 2005 को आयोजित बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। तथापि आयातकों के सुझाव के अनुसार कार्गो के त्वरित हटाए जाने के लिए भूखण्ड के मासिक किराए में 10% रियायत को मंडल ने अनुमोदन प्रदान नहीं किया है।

3.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार यह प्रस्ताव उपयोगकर्ताओं / पत्तन उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि निकायों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था।

3.2. उपयोगकर्ताओं से प्राप्त टिप्पणियों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति पीपीटी को प्रतिपूरक सूचना के रूप में भेजी गई थी।

4. प्रस्ताव की प्रारम्भिक जाँच पड़ताल पर यह पाया गया कि प्रस्ताव के कुछ बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचनाओं / स्पष्टीकरणों की आवश्यकता थी। पीपीटी ने इस संबंध में हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। हमारे प्रश्न और पीपीटी के उत्तर सारणीबद्ध रूप में नीचे दिए गए हैं:

क्रमांक	हमारे प्रश्न	पीपीटी के उत्तर																																																																			
(i)	पीपीटी ने बताया है कि प्रस्तावित व्यवस्था पर उपयोगकर्ताओं से चर्चा हुई थी और उपयोगकर्ता अर्धदण्ड की प्रस्तावित दरों तथा कार्गो को त्वरित खाली करने के लिए भूखण्ड के मासिक किराए पर 10% रियायत पर सहमत हो गए थे । । इसके बाद, पीपीटी ने अर्धदंड की प्रस्तावित दरों को तदर्थ आधार पर कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है । इस संदर्भ में, पीपीटी से अनुरोध है कि वह निम्नलिखित को स्पष्ट करे / प्रस्तुत करे:	10% रियायत के लिए न्यासीमंडल सहमत नहीं हुआ, इसलिए इसे छोड़ना पड़ा । अर्धदण्ड/अचल उपकर लगाने का आधार, आयातक को अपना आयातीत कार्गो पत्तन प्रतिबंधित क्षेत्र से शीघ्र हटाने के लिए बाध्य करना है । ऐसा समझा जाता है कि इस प्रकार के अर्धदण्ड का प्रावधान कोलकाता पत्तन न्यास स्थित हात्विद्या डॉक परिसर में प्रचलित है । वहाँ अर्धदण्ड पहले सप्ताह के लिए रु. 50/- प्रति टन प्रतिदिन है और दूसरे सप्ताह तथा उसके आगे की अवधि के लिए रु. 100/- प्रति टन प्रतिदिन है ।																																																																			
(क)	आयातीत कार्गो को त्वरित खाली किए जाने पर भूखण्ड के मासिक भाड़े में सहमत 10% की रियायत प्रस्तावित न किए जाने का कारण ।																																																																				
(ख)	आयातीत कार्गो विलम्ब से खाली किए जाने के लिए अर्धदण्ड की प्रस्तावित दरों का आधार और उनकी गणना ।																																																																				
(ii)	पीपीटी से अनुरोध है कि वह पिछले 3 वर्षों में प्रहस्ति कोक और कोकिंग कोल के आयातीत कार्गो की वास्तविक मात्रा और समय अवधिके प्रस्तावित पायदानों में प्रतिवर्ष लगे औसत समय का विवरण प्रस्तुत करें ।	<table><tr><th></th><th>प्रहस्ति कुल मात्रा</th><th colspan="5">— दिनों में हटाया गया</th></tr><tr><th>कोकिंग कोल</th><th>लाख टन में</th><th>45 दिनों में</th><th>46-90 दिन में</th><th>91 से 120 दिन में</th><th>120 दिन से अधिक</th></tr><tr><td>2002-03</td><td>18.68</td><td>58%</td><td>35%</td><td>6%</td><td>1%</td></tr><tr><td>2003-04</td><td>22.23</td><td>68%</td><td>28%</td><td>3%</td><td>1%</td></tr><tr><td>2004-05</td><td>32.00</td><td>75%</td><td>19%</td><td>5%</td><td>1%</td></tr><tr><td>2005-06 अपेक्षित</td><td>35.00</td><td>75%</td><td>20%</td><td>4%</td><td>1%</td></tr><tr><td>हार्ड कोक</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2002-03</td><td>5.31%</td><td>68%</td><td>25%</td><td>5%</td><td>2%</td></tr><tr><td>2003-04</td><td>6.00</td><td>59%</td><td>28%</td><td>10%</td><td>3%</td></tr><tr><td>2004-05</td><td>4.34</td><td>59%</td><td>14%</td><td>19%</td><td>8%</td></tr><tr><td>2005-06 अपेक्षित</td><td>5.00</td><td>60%</td><td>20%</td><td>15%</td><td>5%</td></tr></table>		प्रहस्ति कुल मात्रा	— दिनों में हटाया गया					कोकिंग कोल	लाख टन में	45 दिनों में	46-90 दिन में	91 से 120 दिन में	120 दिन से अधिक	2002-03	18.68	58%	35%	6%	1%	2003-04	22.23	68%	28%	3%	1%	2004-05	32.00	75%	19%	5%	1%	2005-06 अपेक्षित	35.00	75%	20%	4%	1%	हार्ड कोक						2002-03	5.31%	68%	25%	5%	2%	2003-04	6.00	59%	28%	10%	3%	2004-05	4.34	59%	14%	19%	8%	2005-06 अपेक्षित	5.00	60%	20%	15%	5%
	प्रहस्ति कुल मात्रा	— दिनों में हटाया गया																																																																			
कोकिंग कोल	लाख टन में	45 दिनों में	46-90 दिन में	91 से 120 दिन में	120 दिन से अधिक																																																																
2002-03	18.68	58%	35%	6%	1%																																																																
2003-04	22.23	68%	28%	3%	1%																																																																
2004-05	32.00	75%	19%	5%	1%																																																																
2005-06 अपेक्षित	35.00	75%	20%	4%	1%																																																																
हार्ड कोक																																																																					
2002-03	5.31%	68%	25%	5%	2%																																																																
2003-04	6.00	59%	28%	10%	3%																																																																
2004-05	4.34	59%	14%	19%	8%																																																																
2005-06 अपेक्षित	5.00	60%	20%	15%	5%																																																																

5. इस प्रकरण में संयुक्त सुनवाई 24 मई 2005 को पीपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में पीपीटी और संबंधित उपयोगकर्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे।

6. इस प्रकरण से संबंधित परामर्शी प्रक्रिया इस प्राधिकरण के कार्यालय के रिकार्डों में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों और उनके द्वारा संयुक्त सुनवाई में दिए गए तर्कों के सारांश संबंध पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे। ये विवरण हमारे वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध है।

7. इस प्रकरण पर प्रक्रिया के दौरान संग्रहित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उमरती है।

(i) पीपीटी शर्तों और निबंधनों के दो अलग-अलग सेटों, यथा, (i) पारगमन शर्तों और (ii) किराया शर्तों पर कार्गो के भंडारण की अनुमति देता है। पारगमन शर्तों के अंतर्गत विलम्ब शुल्क कार्गो के यूनिट पर, विनिर्दिष्ट निःशुल्क अवधि के बाद साप्ताहिक पायदान के आधार पर लगाया जाता है।

किराया शर्तों के अन्तर्गत, पत्तन खुली/ढकी हुई जगह में कार्गो के भंडारण के लिए उपयोगकर्ताओं को लाइसेंस जारी करता है और यह लाइसेंस एक साल के लिए वैध है। लाइसेंस शुल्क आर्बिट्रल क्षेत्र पर मासिक आधार पर लगाया जाता है। एक वर्ष से कम अवधि के लाइसेंसों के लिए पीपीटी निर्धारित लाइसेंस शुल्क पर 10% सरचार्ज लगाता है। किराया शर्तों में रु. 2000/- प्रति माह या उसके बाग की अधिकतम दर पर पारगमन शौडो की लाइसेंसिंग सम्मिलित है। यदि किराया शर्तें एक वर्ष से कम अवधि के लिए हैं तो 10% सरचार्ज के अलावा विलम्ब शुल्क लगे का कोई प्रावधान नहीं है।

(ii) आरम्भ में पत्तन और उपयोगकर्ता, कार्गो को खाली करने में होने वाले विलम्ब के लिए अर्धदंड की दरों पर और कार्गो के त्वरित खाली करने के लिए प्रोत्साहन की दरों पर कथित रूप से सहमत हो गए हैं। किन्तु संदर्भित प्रस्ताव, उपयोगकर्ताओं के साथ कथित सहमति से भिन्न है। पत्तन ने आयातीत कार्गो त्वरित खाली किए जाने के लिए, मुख्यध्व के मासिक भाड़े में रियायत की सहमत दर प्रस्तावित नहीं की है। पीपीटी द्वारा सहमत स्थिति से मुकरने का अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है।

(iii) यह प्रस्ताव यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता से पैदा होता है कि पत्तन का प्रचालनीय क्षेत्र इष्टतम मात्रा में उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें खिचपिच या स्थानान्तरण से पोतों से होने वाली उत्तराई दुष्प्रभावित होती है। यह प्राधिकरण इस स्थिति का निःसंकोच समर्थन करता है। वास्तव में, इस प्रकार की खिचपिच (स्थानान्तरण) को दूर करने के लिए मूल्य-निर्धारण अन्यत्र, अनेक मामलों में किया गया है। तथापि यह ध्यान में रखना है कि निर्धारित की जाने वाली प्रशुल्क व्यवस्था अनुपालित सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए।

पोत परिवहन, राड़क आवागमन और राजगार्ग मंत्रालय (एमएसआरटीएम) से प्राप्त निदेशों के अनुपालन में इस प्राधिकरण ने संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शी 31 मार्च 2005 को अधिसूचित कर दिए हैं। पीपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क व्यवस्था, इसीलिए संशोधित मार्गदर्शियों के प्रकाश में ही विश्लेषित की जानी चाहिए। यहाँ यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि यह प्रस्ताव किराया संबंधी शर्तों और विलम्ब शुल्क का मिश्रण है। प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 4.6, उपयोगकर्ताओं को पट्टे पर दिए हुए / किराए पर दिए हुए प्रचालनीय क्षेत्र में भंडारित कार्गो पर विलम्ब शुल्क लगाने की अनुमति नहीं देता। चूंकि यह प्रस्ताव प्रशुल्क मार्गदर्शियों के अनुरूप नहीं है इसलिए इसे अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा सकता है।

(iv) पोत संबंधी और कार्गो संबंधी, दोनों प्रमारों के बारे में पीपीटी के दरमान को इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार अप्रैल 2000 में संशोधित किया गया था और पीपीटी को, प्रचालनीय क्षेत्र में परिसम्पत्तियों के किराया, उपस्कर भाड़ा प्रमार और पारादीप फोस्पेट लिमिटेड (पीपीएल) के नियंत्रण वाली बर्थ के लिए प्रमार समेत परिसम्पत्तियों के किरायों से संबंधित अन्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत करने थे। पीपीटी के मैकेनिकल कोल हैंडलिंग प्लान (एमसीएचपी) के प्रशुल्क के लिए पीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 15 मार्च 2005 के अपने आदेश में इस प्राधिकरण ने पहले ही, अपने दरमान की समीक्षा के लिए पीपीटी को व्यापक प्रस्ताव तैयार करने की और अपना प्रस्ताव 30 सितम्बर 2005 तक दाखिल करने की सलाह दी है। पीपीटी संदर्भित प्रस्ताव की समीक्षा कर सकता है और जैसाकि वह सहमत हुआ था, अपने व्यापक प्रस्ताव में प्रशुल्क को सामान्य समीक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था शामिल कर सकता है।

(v) जैसाकि पहले बताया गया है, पीपीटी ने, आयातीत कार्गो को खाली करने में होने वाले विलम्ब के लिए अर्धदण्ड की प्रस्तावित दर तदर्थ आधार पर लागू करने का निर्णय लिया है। चूंकि संदर्भित प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया है, पीपीटी को परमर्श दिया जाता है कि यदि उसने उपयोगकर्ताओं से कोई अर्धदंड प्रमार लिया हो तो उसे लौटा दे।

7. परिणाम स्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से और समग्र विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण पीपीटी के प्रस्ताव को अस्वीकार करता है और पीपीटी को, प्रस्तावित प्रशुल्क व्यवस्था के आधार पर पत्तन द्वारा लगाए गए यदि कुछ लगाया गया हो, अर्धदण्ड प्रमार को वापिस करने का निदेश देता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[ विज्ञापन III/IV/143/2005-असा. ]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****NOTIFICATION**

Mumbai, the 11th July, 2005

**No. TAMP/29/2005-PPT.**—In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal of the Paradip Port Trust to levy penalty/non-moving cess for inordinate delay in evacuation of imported coke and coking coal from the port as in the Order appended hereto.

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

Case No. TAMP/29/2005-PPT

The Paradip Port Trust

Applicant

**ORDER**

(Passed on this 15th day of June, 2005)

This case relates to a proposal received from the Paradip Port Trust (PPT) to levy penalty/ non-moving cess for inordinate delay in evacuation of imported coke and coking coal from the port.

2. The main points made by PPT are as follows:
- (i). The Port has been experiencing congestion in storage yards/ plots on account of inordinate delay in evacuation of imported coal and coke by importers/ exporters.
  - (ii). The Major Port Trusts Act empowers the Port Trust to auction the import cargo if not evacuated from the port within a period of 60 days. Taking such an action may invite severe flaks from exporting/ importing community. Thus, left with no other option, the PPT has come up with this proposal.
  - (iii). The PPT has consulted the importers of coal and coking coal in the meeting held on 7 October 2004 for introduction of penalty for delay in evacuation of cargo and concession for early removal of cargo. According to the port, the users have agreed to the rates of penalty and rate of concession.
  - (iv). The PPT proposes to levy the following penalty/ non-moving cess for inordinate delay in evacuation of imported coke and coking coal from the Port and recovery of charges will commence on adhoc basis.

Period of evacuation	Penalty/ non moving cess
Within 45 days of completion of vessel	-NIL-
46 <sup>th</sup> day to 90 <sup>th</sup> day	Rs.5/- per ton
91 <sup>st</sup> day to 120 <sup>th</sup> day	Rs.10/- per ton
Beyond 121 <sup>st</sup> day	Rs.20/- per ton

- (v). (a). The revenue generation, in this regard, for 2005-06 and 2006-07 has been calculated on the basis of the following average evacuation of cargo from the port:
  - (a). Within 45 days - 80%
  - (b). Within 45 – 90 days - 10%
  - (c). Within 91 – 120 days - 8%
  - (d). Within 121 days above - 2%
- (b). The revenue generation on account of the proposed levy of penalty is as follows:

Year 2005-06	-	Rs.62.90 Lakhs
Year 2006-07	-	Rs.68.00 Lakhs

- (vi). The Board of Trustees of PPT have approved the proposal in the meeting held on 25 January 2005. However, the 10% concession on monthly plot rent for faster evacuation of cargo as suggested by the importers is not approved by the Board.

3.1. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal was forwarded to users / representative bodies of port users for their comments.

3.2. A copy each of the comments received from the users was forwarded to PPT as feed back information.

4. On a preliminary scrutiny of the proposal, it was found that additional information/ clarifications were required on some of the points of the proposal. The PPT has responded to our queries in this regard. Our queries and the response of PPT are tabulated below:

Sr.No	Our queries	Response of PPT					
(i).	The PPT has stated that the proposed arrangement was discussed with the users and the users agreed to the proposed rates of penalty and concession of 10% of monthly plot rent for faster evacuation of imported cargo. Further, the PPT has proposed to implement the proposed rates of penalty on ad-hoc basis. In this context, the PPT is requested to clarify/ furnish the following:	The Board of Trustees did not agree to the 10% concession and hence it was dropped. The basis for imposing penalty/ non-moving cess is to compel the importer to evacuate cargo from the port prohibited area early. It is understood that such a penalty clause is in vogue in Haldia Dock Complex at Kolkata Port Trust where penalty ranges from Rs.50/- per ton per day for the first week and Rs.100/- per ton per day from second week onwards.					
(a).	The reason for not proposing the agreed concession of 10% on monthly plot rent for faster evacuation of imported cargo.						
(b).	The basis and working for the proposed rates of penalty for delay in evacuation of imported cargo.						
(ii).	The PPT is requested to furnish the actual quantum of imported cargo of coke and coking coal handled during the past 3 years and the year wise average dwell time in the proposed slabs of time period.		Total Quantity handled	Despatch within			
		Coking Coal	In lakh tonnes	45 days	46-90 days	91-120 days	Beyond 120 days
		2002-03	18.68	58%	35%	6%	1%
		2003-04	22.23	68%	28%	3%	1%
		2004-05	32.00	75%	19%	5%	1%
		2005-06 (anticipated)	35.00	75%	20%	4%	1%
		Hard coke					
		2002-03	5.31	68%	25%	5%	2%
		2003-04	6.00	59%	28%	10%	3%
		2004-05	4.34	59%	14%	19%	8%
		2005-06 (anticipated)	5.00	60%	20%	15%	5%

5. A joint hearing in this case was held on 24 May 2005 at the PPT premises. At the joint hearing, the PPT and the concerned users have made their submissions.

6. Proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties at the joint hearing will be sent separately to the relevant parties. These details are also available at our website <http://tariffauthority.gov.in>

2129 917 2005-2

7. With reference to the totality of the information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). The PPT allows storage of cargo on two different set of terms and conditions, viz., (i) transit terms; and, (ii) rental terms. Under transit terms, demurrage is levied on unit of cargo on a weekly slab basis beyond the specified free period.

Under rental terms, the port issues licenses to users for storage of cargo in the open / covered space and the license is valid for one year. License fee is levied for the area allotted on a monthly basis. For the licenses of less than one year, the PPT levies a surcharge of 10% on the prescribed licence fee. The rental terms also include licensing of transit sheds at a maximum rate of Rs.2000 per month or part thereof. If the rental terms are for a shorter period of less than one year, there is no provision to levy demurrage other than the 10% surcharge.

- (ii). Initially, the port and the users have reportedly agreed on the rates of penalty for delay in evacuation of cargo as well as incentive for faster evacuation of cargo. But, the proposal in reference is at variance with the reported agreement with the users. The port has not proposed the agreed rate of concession in the monthly plot rent for faster evacuation of imported cargo. The departure by PPT from the agreed position remains unexplained.
- (iii). The proposal stems from the necessity to ensure that operational area of the port is optimally utilised as congestion therein would affect vessel productivity. This Authority unreservedly endorses this position. In fact, such a congestion pricing has been approved by this Authority in many cases elsewhere. Nevertheless, it is to be borne in mind that the tariff arrangement to be prescribed should be in line with the general principles followed.

In compliance with the direction from the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways (MSRTH), this Authority has notified the revised tariff guidelines on 31 March 2005. The tariff arrangement proposed by PPT should therefore be analysed in the light of the revised guidelines. It may be relevant here to note that the proposal is a mix of rental terms and demurrage. Clause 4.6 of the tariff guidelines does not permit levying of demurrage on cargo stored in the operational area leased / licensed on rental to users. The proposal cannot, therefore, be approved as it is not in accordance with the tariff guidelines.

- (iv). The Scale of Rates of PPT in respect of both vessel related and cargo related charges was last revised by this Authority in April 2000; and, the PPT was also to submit the other proposals relating to the asset rentals including rentals for properties in operational area, equipment hire charges and charges for Paradip Phosphate Limited (PPL) captive berth. This Authority in its Order dated 15 March 2005 relating to a proposal received from the PPT for tariff of the Mechanical Coal Handling Plant (MCHP) of PPT, has already advised to formulate a comprehensive proposal for review of its Scale of Rates and file its proposal by 30 September 2005. The PPT can review the proposal in reference and include a suitable arrangement in its comprehensive proposal for general review of tariff, as agreed by it.
- (v). As stated earlier, the PPT has decided to implement the proposed rate of penalty for delay in evacuation of import cargo on ad-hoc basis. Since the proposal in reference is not approved, the PPT is advised to refund the penal charges, if any, collected from the users.

In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority rejects the proposal of PPT and directs the PPT to refund the penal charges, if any, levied by the port based on the proposed tariff arrangement.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT. III/IV/143/2005-Exty.]